



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032023-244080  
CG-DL-E-02032023-244080

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 992]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2023/फाल्गुन 11, 1944

No. 992]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2023/PHALGUNA 11, 1944

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(बजट प्रभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2023

## पूर्व अवधि समायोजनों पर भारत सरकार लेखा मानक

**का.आ. 1033(अ).**—चूंकि नकद आधार पर लेखांकन त्रुटियों के सुधार या एक या अधिक पूर्व अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों के समायोजन के लिए पूर्व अवधि मदों को मान्यता देना है, जिसके लिए खाते बंद कर दिए गए हैं;

और चूंकि, पूर्व अवधि समायोजनों को विवरण संख्या 5 (केंद्रीय वित्त खातों में) और विवरण संख्या 13 (कुछ राज्य वित्त खातों में) के एक भाग के रूप में 'शेष राशि के सारांश' के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है;

और चूंकि, केंद्रीय वित्त खाते में पूर्व अवधि समायोजन सिविल लेखा मैनुअल के पैराग्राफ 5.15.3 द्वारा शासित होता है, लेकिन राज्यों में "महालेखाकार के लिए लेखा कोड" में ऐसा कोई नियम नहीं है;

और चूंकि, राज्यों के विभिन्न वित्त खातों के अध्ययन में, यह देखा गया था कि अधिकांश राज्य अपने खातों में पूर्व अवधि समायोजन का संज्ञान नहीं ले रहे हैं या पूर्व अवधि समायोजन को सही करने के लिए स्थानांतरण प्रविष्टियों को पारित करने की गलत प्रथा का पालन नहीं कर रहे हैं;

और चूंकि, वर्तमान मानक का उद्देश्य न केवल ऐसी जानकारी का खुलासा करना है जो पूर्व अवधि की त्रुटियों से संबंधित है, बल्कि सरकारी निर्णयों में परिवर्तन से उत्पन्न पूर्व अवधि समायोजन की आवश्यकता वाली प्रविष्टियों को भी शामिल करता है जो पिछले वर्षों के दौरान वर्तमान शेष राशि और प्रगतिशील राशि को प्रभावित कर सकते हैं, जिनके लिए खाते बंद कर दिए गए हैं।

अब, अतः, संविधान के अनुच्छेद 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सुझाव पर, निम्नलिखित लेखा मानक बनाते हैं, अर्थात् :-

क. संक्षिप्त शीर्षक - इन लेखा मानकों को भारतीय सरकार लेखा मानक (आईजीएस) 4- पूर्व अवधि समायोजन कहा जा सकता है।

#### ख. उद्देश्य.-

इस मानक का उद्देश्य उस तरीके को निर्धारित करना है जिसमें एक बार पहचान की गई त्रुटियों सहित पूर्व अवधि समायोजन को लेखांकन के नकद आधार के तहत वर्तमान अवधि (वित्तीय वर्ष) में प्रस्तुत और प्रकट किया जाएगा।

#### ग. विस्तार.-

- (1) यह मानक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगा जो लेखांकन के नकद आधार के तहत वित्तीय विवरण तैयार करता है और प्रस्तुत करता है; जो क्रमशः संसद, राज्य विधानमंडल और विधानमंडल के साथ केंद्र शासित प्रदेश के समक्ष रखे जाते हैं।
- (2) पूर्व अवधि समायोजन का संज्ञान लेते समय इस मानक में वेतन में वृद्धि अथवा पेंशन में संशोधन अथवा महंगाई भत्तों में वृद्धि आदि के कारण उत्पन्न होने वाले बकायों के भुगतान जैसे लेन-देन शामिल नहीं हैं। वर्तमान अवधि में, हालांकि वे पूर्व अवधि से संबंधित हैं क्योंकि इन लेनदेन को किसी भी प्रकार की त्रुटियों या सरकारी नीतियों में किसी भी समायोजन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- (3) इस मानक में आईजीएस-2 और आईजीएस-3 में विशेष रूप से निपटाए गए ऋणों और सहायता अनुदानों की चूक को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि यह केवल पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों के सुधार या समायोजन की प्रक्रिया है।

#### घ. परिभाषाएँ

- (क) "लेखा प्राधिकरण" से वह प्राधिकरण अभिप्रेत है जो सरकारों के वित्तीय विवरण तैयार करता है;
- (ख) "पूंजीगत व्यय" का अर्थ है भविष्य के लाभों को बनाने के लिए किया गया व्यय जैसे भूमि, भवन, मशीनें, मौजूदा सुविधाओं या परिसंपत्तियों का उन्नयन और इसमें मूल्य जोड़ने के लिए मौजूदा सुविधाओं या परिसंपत्तियों का उन्नयन और इसमें सरकार द्वारा दिए गए शेषों और ऋणों और अग्रिमों में निवेश शामिल है;
- (ग) "सरकारों के सामान्य उद्देश्य वित्तीय विवरण" का अर्थ है (i) सरकार के वित्त खाते; (ii) विनियोग लेखा; और (iii) वास्तविक और बजटीय प्राप्तियों का विवरण;
- (घ) "सरकार" का अर्थ है सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों का एक साथ होना, चाहे वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश सरकार के हों;
- (ङ) "शेष राशि के लिए बंद शीर्ष" वे शीर्ष हैं जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए शेष राशि को आगे बढ़ाने के बाद से अथ और इति शेष होते हैं;
- (च) "सरकारी खातों के लिए बंद शीर्ष" वे शीर्ष हैं जिनमें पिछले वित्तीय वर्ष के इति शेष से आगे कोई अथ शेष नहीं है;

- (छ) "पूर्व अवधि" का अर्थ है एक या अधिक पूर्व वित्तीय वर्ष जिनके लिए खाते पहले से ही बंद हैं;
- (ज) "पूर्व अवधि समायोजन" का अर्थ है सरकार के निर्णयों में परिवर्तन के कारण त्रुटियों या समायोजनों को सुधारना जो पिछले वर्षों की शेष राशि और क्रमिक बुकिंग को प्रभावित कर सकता है, जिसके लिए खाते बंद कर दिए गए हैं;
- (झ) "पूर्व अवधि की त्रुटियाँ" विश्वसनीय जानकारी का उपयोग करने में विफलता, या दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली एक या अधिक पूर्व अवधियों के लिए संस्था के वित्तीय विवरणों में चूक और गलत विवरण हैं -
- (i) जो तब उपलब्ध था जब वित्तीय विवरण उन अवधियों के लिए जारी करने के लिए अधिकृत थे; और
  - (ii) यथोचित रूप से जिनके प्राप्त होने की उम्मीद की जा सकती है और उन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में ध्यान में रखी जा सकती है और ऐसी त्रुटियों में गणितीय गलतियों के प्रभाव, लेखांकन नीतियों को लागू करने में गलतियाँ, निरीक्षण या तथ्यों की गलत व्याख्या शामिल है;
- (ञ) "रिपोर्टिंग तिथि" वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, अर्थात् 31 मार्च;
- (ट) "राजस्व व्यय" का अर्थ अनुरक्षण, मरम्मत, रखरखाव और कार्यचालन व्यय के लिए सभी शुल्क हैं, जो आस्तियों को एक चलते क्रम में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं और साथ ही प्रतिष्ठान और प्रशासनिक खर्चों सहित संस्था के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी खर्च भी हैं;

ड. प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ:-

(1) पूर्व अवधि समायोजन निम्नलिखित जानकारी वाले अनुबंध 1 से 3 के अनुसार प्रस्तुत और प्रकट किए जाएंगे:-

(क) पूर्व अवधि समायोजन या त्रुटि की प्रकृति;

(ख) प्रस्तुत प्रत्येक पूर्व अवधि के लिए, व्यावहारिक सीमा तक, प्रभावित प्रत्येक वित्तीय विवरण पंक्ति मद के लिए समायोजन या त्रुटि के सुधार की राशि;

(ग) व्यावहारिक सीमा तक, प्रस्तुत की गई प्रारंभिक पूर्व अवधि की शुरुआत में त्रुटि सुधार या समायोजन की राशि; और

(घ) एक स्पष्टीकरण यदि यह उचित प्रयासों से उपरोक्त खंड (ख) या खंड (ग) में प्रकट की जाने वाली राशि निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है।

(2) केंद्रीय वित्त खातों और राज्य वित्त खातों के संबंध में, मानक के अनुबंध 1 से 3 में दर्शाए गए अनुसार इन प्रकटनों को संलग्न किया जाएगा।

(3) "शेष राशि का सारांश" अनुबंध 1 के अनुसार केंद्रीय वित्त खातों के विवरण-5 से है जो सरकारी खातों में कुल पूर्व अवधि समायोजन को दर्शाता है और इस मानक के अनुबंध 2 से लिया गया है।

(4) शेष राशि के बंद शीर्षों पर समेकित डेबिट या क्रेडिट प्रभाव को संघ या राज्य सरकार के वित्त खातों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार की गई शेष राशि के सारांश के सरकारी खातों में क्रेडिट या डेबिट के रूप में लिया जाना है।

(5) अनुबंध 2 सरकारी निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रकट करता है, जिसमें सभी लेखा शीर्षों को शामिल करते हुए पूर्व अवधि में समायोजन और त्रुटियों की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें सरकारी खातों के लिए बंद शीर्षों को छोड़कर उनके शीर्ष या लघु दोनों प्रभावित खातों के मुख्य या लघु शीर्षवार विवरण शामिल हैं, जिनमें ऐसे मामले शामिल हो सकते हैं:

- (i) ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करना और इसके विपरीत, ऋणों को सहायता अनुदान में परिवर्तित करना और इसके विपरीत, सरकारी निर्णयों के कारण उत्पन्न होते हैं, जो उन पर राशियों के प्रविष्टियों के बंद शीर्ष को प्रभावित कर सकते हैं;
- (ii) ऋणों को इक्विटी में और इसके विपरीत बदलने की स्वीकृति के बाद भी, ऋणों को सहायता अनुदान में और इसके विपरीत परिवर्तित करने आदि जारी किए जाने के बाद भी (जैसा कि ऊपर खंड (i) में संदर्भित है) और कोई भी इकाई पिछले शीर्षों के तहत व्यय दर्ज करना जारी रखती है, तो ऐसे मामलों को 'त्रुटि' माना जाएगा;
- (iii) ऐसे मामले जिनमें सरकार के निर्णय या मंजूरी के कारण ब्याज नहीं देने वाले बाजार ऋणों से निर्वहन किए गए ऋणों की शेष राशि को बाजार ऋणों में स्थानांतरित करने के लिए पूर्व अवधि समायोजन शामिल है;
- (iv) पूर्व अवधि में दो ऋण शीर्षों के बीच गलत वर्गीकरण से जुड़े मामले जो सुधार के बाद वर्तमान अवधि में उनके अथ शेष को प्रभावित कर सकते हैं।
- (6) अनुबंध 3 पूंजीगत व्यय शीर्षों, यदि कोई हो, को शामिल करते हुए पूर्व अवधि समायोजन का पूंजीगत व्यय पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है।
- (7) यदि सरकार के बंद शीर्षों में पूंजीगत व्यय शीर्ष शामिल हैं, तो ये मामले पूंजीगत व्यय शीर्षों को प्रभावित करते हैं जिन्हें अनुबंध 3 में इंगित करने की आवश्यकता होती है और इसके प्रभाव को सरकार के सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के उपयुक्त विवरणों में लिया जाना चाहिए।

#### च. महत्वपूर्ण

पूर्व अवधि समायोजन को महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि इसका मूल्य स्पष्ट तौर पर एक हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक व्यक्त किया जा सकता हो।

#### छ. प्रभावी तिथि

यह भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस) 4 - पूर्व अवधि समायोजन 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरण के लिए प्रभावी होगा।

[फा. सं. 1(32)-बी(एसी)/2022]

भारत की राष्ट्रपति के आदेश से,

आशीष वछानी, अपर सचिव

#### पूर्व अवधि समायोजन

##### अनुबंध 1

##### शेष राशि का सारांश (सरकारी खाते)

(₹ हजारों में)

जमा	व्यौरा	उधार
	क. प्रारंभिक शेष राशि	
ZZ*	ख. पूर्व अवधि समायोजन का शुद्ध प्रभाव	ZZ*
	ग. प्राप्त शीर्ष (राजस्व खाता)	
	घ. प्राप्त शीर्ष (पूंजी खाता)	
	ङ. व्यय शीर्ष (राजस्व खाता)	
	च. व्यय शीर्ष (पूंजी खाता)	

[illegible]

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**(BUDGET DIVISION)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2023

**Indian Government Accounting Standard on Prior Period Adjustments.**

**S.O. 1033(E).**—Whereas, accounting on cash basis recognises prior period items for rectification of errors or adjustment of financial statements for one or more prior periods for which the accounts have been closed;

And whereas, Prior Period Adjustments are being presented as a part of Statement No. 5 (in Union Finance Accounts) and Statement No. 13 (in some State Finance Accounts) as 'Summary of Balances';

And whereas, the Prior Period Adjustments in Union Finance Account is governed by the Paragraph 5.15.3 of the Civil Accounts Manual but in States there are no such rules in "Accounts code for Accountant General";

And whereas, in a study of various Finance Accounts of States, it was observed that majority of the States are not taking cognizance of Prior Period Adjustments in their accounts or following a wrong practice of passing transfer entries to correct Prior Period Adjustments;

And whereas, the present Standard not only aims to disclose such information which pertains to prior period errors but also covers entries requiring Prior Period Adjustments arising out of changes in Government decisions which may impact current balances and progressive amounts during the earlier years for which accounts have been closed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 150 of the Constitution, the President, on the advice of the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following accounting standards, namely: -

A. Short title. - These accounting standards may be called the Indian Government Accounting Standards (IGAS) 4 - Prior Period Adjustments.

**B. Objective.-**

The objective of this Standard is to prescribe the manner in which Prior Period Adjustments including errors once identified shall be presented and disclosed in the current period (the financial year) under the cash basis of accounting.

**C. Scope.-**

- (1) *This Standard will apply to Union Government, State Government and Union territory with Legislature which prepares and presents financial statements under the cash basis of accounting; which are laid before the Parliament, State Legislature and Union territory with Legislature, respectively.*
- (2) *This Standard while taking cognizance of Prior Period Adjustments does not include transactions such as payment of arrears arising due to increase in salaries or revision of pension or increase in dearness allowance, etc. in the current period though they belong to prior periods as these transactions cannot be attributed to any type of errors or any adjustment in Government Policies.*
- (3) *This Standard shall not include in its ambit, defaults of loans and grants-in-aid dealt in IGAS-2 and IGAS-3 exclusively as it is only a process for rectification or adjustment of financial statements of prior periods.*

**D. Definitions**

- (a) *"Accounting Authority" means the authority which prepares the financial statements of the Governments;*
- (b) *"Capital Expenditure" means an expenditure incurred to create future benefits like acquisition of tangible assets of material and permanent nature such as land, building, machines, upgradation of the existing facilities or assets to add values to the same and includes investment in shares and loans and advances given by the Government;*
- (c) *"General Purpose Financial Statements of Governments" means (i) Finance Accounts of the Government; (ii) Appropriation Accounts; and (iii) Statement on actual and budgeted receipts;*
- (d) *"Government" means all departments and ministries of a Government taken together, whether of the Union Government or State Government or of Union territory Government with Legislature;*

- (e) *"Heads closed to Balances" are the heads in which there are opening and closing balances since the balances are carried forward to the next financial year;*
- (f) *"Heads closed to Government Accounts" are the heads in which there are no opening balances carried forward from the closing balance of previous financial year;*
- (g) *"prior period" means one or more prior financial years for which accounts are already closed;*
- (h) *"Prior Period Adjustment" means rectification of errors or adjustments due to change in the Government decisions which may affect balances and progressive bookings of earlier years for which accounts have been closed;*
- (i) *"Prior period errors" are omissions from, and mis-statements in, the entity's financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use, or misuse of, reliable information-*
  - (i) *which was available when financial statements for those periods were authorised for issue; and*
  - (ii) *which could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in the preparation and presentation of those financial statements and such errors include the effects of mathematical mistakes, mistakes in applying accounting policies, oversights or misinterpretations of facts;*
- (j) *"Reporting Date" is the last day of the financial year to which the financial statements relate that is to say, the 31<sup>st</sup> March;*
- (k) *"Revenue Expenditure" means all charges for maintenance, repair, upkeep and working expenses, which are required to maintain the assets in a running order as also all other expenses incurred for the day to day running of the entity, including establishment and administrative expenses;*

#### **E. Presentation and Disclosure Requirements.-**

- (1) *Prior Period Adjustments shall be presented and disclosed in accordance with Annexures 1 to 3 containing the following information, namely:-*
  - (a) *the nature of the Prior Period Adjustment or error;*
  - (b) *for each prior period presented, to the extent practicable, the amount of the adjustment or correction of error for each financial statement line item affected;*
  - (c) *to the extent practicable, the amount of the error correction or adjustment at the beginning of the earliest prior period presented; and*
  - (d) *an explanation if it is not practicable to determine with reasonable efforts the amounts to be disclosed in clause (b) or clause (c) above.*
- (2) *With regard to the Union Finance Accounts and State Finance Accounts, these disclosures as shown in Annexures 1 to 3 of the Standard will be attached.*
- (3) *The "Summary of Balances" at Annexure 1 is from Statement-5 of the Union Finance Accounts which reflects total Prior Period Adjustments in Government Accounts and is derived from Annexure 2 of this Standard.*
- (4) *The consolidated debit or credit impact on the Heads closed to Balances has to be taken as credit or debit in Government Accounts of the Summary of Balances prepared as at the end of each financial year in the Finance Accounts of the Union or the State Government.*
- (5) *Annexure 2 discloses information related to Government decisions which may require adjustments and errors in prior period involving all Heads of Accounts including their Major or Minor head wise details of both the affected heads of account involved except heads Closed to Government Accounts which may include cases such as:*
  - (i) *conversion of Loans to equity and vice versa, conversion of loans to grants-in-aid and vice versa etc., arising due to Government decisions which may impact Head closed to Balances entries thereon;*
  - (ii) *even after sanction for conversion of loans to equity and vice versa, conversion of loans to grants-in-aid and vice versa etc., issued (as referred in clause (i) above) and any entity continues to book expenditure under previous heads then such cases will be considered as 'Error';*
  - (iii) *cases involving Prior Period Adjustment to transfer balance of discharged loans from Market Loans bearing Interest to Market Loans not bearing Interest due to Government decision or sanction;*

- (iv) *cases involving misclassification among two loan heads in the prior period which after correction may impact their opening balances in the current period.*
- (6) *Annexure 3 relates to Impact of Prior Period Adjustments involving Capital Expenditure Heads, if any, on Capital Expenditure.*
- (7) *If the Heads closed to Government involves Capital Expenditure Heads, then these cases affect the Capital Expenditure Heads which needs to be indicated in Annexure 3 and its impact be taken in appropriate statements of General Purpose Financial Statements of Government.*

#### F. Materiality

Prior Period Adjustments shall be considered material if its value can be expressed in clear terms equal to or greater than rupees one thousand.

#### G. Effective date

This Indian Government Accounting Standard (IGAS) 4 - Prior Period Adjustments shall be effective for the financial statement for the periods commencing from the 1<sup>st</sup> day of April, 2023.

[F. No. 1(32)-B(AC)/2022]

By Order of the President of India,

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

#### Prior Period Adjustments

#### Annexure 1 Summary of Balances (Government Accounts)

(₹ in thousands)

Debit	Details	Credit
	A. Opening Balance	
zz*	B. Net effect of Prior Period Adjustments	zz*
	C. Receipt Heads (Revenue Account)	
	D. Receipt Heads (Capital Account)	
	E. Expenditure Heads (Revenue Account)	
	F. Expenditure Heads (Capital Account)	
	G. Inter –State Settlement	
	H. Miscellaneous (Net)	
	I. Transfer to Contingency Fund	
	J. Closing Balance	
XXXX	GRAND TOTAL	XXXX

\*Net effect (Dr. or Cr.) of Prior Period Adjustments in Government Accounts of 'Statement of Summary of Balance' (Annexure 1) will be zz (i.e. difference of xx and yy) given in Annexure 2.

#### Details of Prior Period Adjustments

#### Annexure 2

(₹ in thousands)

Sr.No.	Type of Corrections (Adjustments/Errors)	Heads of Accounts (Major / Minor Heads wise details of both the affected heads of account involved are to be shown.	Carry Forward 'Opening Balance' as on 1.4.20.. (Current FY)		Year-wise prior corrections			Opening Balance as on 1.4.20.. after correction (Current FY)		Remarks if any
					Year of prior period	Amount of Correction				
			Dr.	Cr.		Dr.	Cr.		Dr.	



		separately except heads closed to Govt. Accounts)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											
4											
5											
Total						xx	yy				
Net Effect of Prior Period Adjustment							zz (Difference of xx and yy)				

**Note :** Column (2) "Type of Corrections (Adjustments/Errors)" will also include frauds of any value, if any, which will be mandatorily recorded in Column (9) as 'fraud'.

### Annexure 3

#### Adjustment in Prior Period involving all Heads Closed to Balance vis-à-vis Heads Closed to Government Accounts

Impact of Prior Period Adjustments involving Capital expenditure Heads, if any, on Capital Expenditure

(₹ in thousands)

Sr. No.	Major / Minor Head (Capital Expenditure Heads)	Description of Accounting Head	Expenditure as on 31.3.20... before Adjustments	Year-wise prior corrections			Expenditure incurred till end of the FY.... After adjustments	Remarks if any
				Year/s of prior period, if available	Amount of Correction		Reason of Correction	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Dr	Cr	(8)	(10)
1								
2								